

ग्रीन बॉण्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **भारतीय रजिस्टर बैंक** (Reserve Bank of India- RBI) द्वारा कथि गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में सूचना विषमता (Asymmetric Information) के कारण ग्रीन बॉण्ड जारी करने की लागत प्रायः अन्य बॉण्डों की तुलना में अधिक रही है।

प्रमुख बांदिः

ग्रीन बॉण्ड (विवरण):

- **ग्रीन बॉण्ड के बारे में:**
 - ग्रीन बॉण्ड ऋण प्राप्तिका एक साधन है जसिके माध्यम से ग्रीन 'परियोजनाओं के लयि धन जुटाया जाता है, यह मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परविहन, स्थायी जल प्रबंधन आदि से संबंधित होता है।
 - बॉण्ड जो कार्याय का एक नशिचति साधन होता है, एक नविशक द्वारा उधारकरता (आमतौर पर कॉर्पोरेट या सरकारी) को दयि गए ऋण का प्रतनिधित्व करता है।
 - पारंपरकि बॉण्ड (ग्रीन बॉण्ड के अलावा अन्य बॉण्ड) द्वारा नविशकों को एक नशिचति ब्याज दर (कूपन) का भुगतान कया जाता है।
- **वृद्धि:**
 - वर्ष 2007 में युरोपीय नविश बैंक और **विश्व बैंक** जैसे कुछ बैंकों द्वारा ग्रीन बॉण्ड लॉन्च कया गया। इसके बाद वर्ष 2013 में कॉर्पोरेट्स द्वारा भी इन्हें जारी कया गया जसि कारण इसका समग्र विकास हुआ।
- **विनियमन:**
 - **भारतीय प्रतभित्तिओं और वनियित बोर्ड** (Securities and Exchange Board of India- SEBI) द्वारा ग्रीन बॉण्ड जारी करने एवं इन्हें सूचीबद्ध करने हेतु पारदर्शी मानदंडों को लागू कया गया है।
- **लाभः**
 - **प्रतषिठा में बढ़ोत्तरी:**
 - ग्रीन बॉण्ड जारीकरता की प्रतषिठा को बढ़ाते हैं, क्योंकि यह **सतत विकास** के प्रताउनकी प्रतबिद्धता को प्रदर्शित करने में सहायक है।
 - **प्रतबिद्धताओं की पूरता:**
 - इनमें जलवायु समझौतों और इन पर हस्ताक्षरकरताओं द्वारा अन्य हरति प्रतबिद्धताओं को पूरा करने की क्षमता है।
 - भारत का **राष्ट्रीय सतर पर निर्धारित योगदान** (Intended Nationally Determined Contribution- INDC) दस्तावेज जलवायु सुधार की दशा में भारत के योगदान और प्रगति के लयि एक कम कार्बन पथ का अनुसरण करने के लक्ष्य का उल्लेख करता है।
 - **कम लागत को बढ़ावा:**
 - आमतौर पर वाणिज्यिकि बैंकों द्वारा दयि जाने वाले ऋण की तुलना में ग्रीन बॉण्ड पर कम ब्याज लयि जाता है।
 - हरति नविश विदेशी नविशकों को आकर्षित करने के साथ-साथ पूंजी जुटाने की लागत को कम करने में मदद कर सकता है।
 - **सनराइज सेक्टर**
 - ग्रीन बॉण्ड अक्षय ऊर्जा जैसे सनराइज सेक्टर के वित्तपोषण को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं, इस प्रकार यह भारत के सतत विकास में योगदान देते हैं।

RBI द्वारा कथि गए हालयि अध्ययन का विवरणः

- **वर्तमान शेयरः**
 - वर्ष 2018 के बाद से भारत में जारी सभी प्रकार के बॉण्ड में ग्रीन बॉण्ड का हसिसा मात्र 0.7% रहा है।
 - हालाँकि मार्च 2020 तक गैर-पारंपरकि ऊर्जा के लयि बैंकों द्वारा दयि जाने वाला ऋण, विद्युत क्षेत्र के बकाया कुल बैंक ऋण का लगभग 7.9 प्रतशित है।
 - भारत में ज्यादातर ग्रीन बॉण्ड सार्वजनकि क्षेत्र की इकाइयों या कॉर्पोरेट्स द्वारा बेहतर वित्तीय स्थितिको ध्यान में रखकर

जारी कयि जाते हैं।

- **चुनौतियाँ :**

- **उच्च कूपन दर:**

- 5 से 10 वर्षों के मध्य की परपिकव अवधि के साथ वर्ष 2015 के बाद से जारी कयि गए ग्रीन बॉण्ड के लयि औसत कूपन दर सामान्यतः इसी अवधि की कॉर्पोरेट सरकार (**Corporate Government**) के बॉण्ड की तुलना में अधिक होती है।

- **उधार लेने की उच्च लागत:**

- सूचना वषिमता के कारण यह सबसे महत्वपूर्ण चुनौती रही है। उच्च कूपन दर अधिक उधार लेने की लागत के कारणों में से एक है।
 - सूचना वषिमता, जसि "सूचना वफिलता" के रूप में भी जाना जाता है, की स्थितितिब उत्पन्न होती है जब आरथिक लेन-देन के लयि एक पक्ष के पास दूसरे पक्ष की तुलना में अधिक भौतिक ज्ञान होता है।

- **सुझाव:**

- भारत में एक बेहतर सूचना प्रबंधन प्रणाली वकिसति करने से परपिकवता असमानता को कम करने, उधार लेने की उच्च लागत और विभिन्न चरणों में उधार लेने की लागत और संसाधनों के कुशल आवंटन में मदद मलि सकती है।

अन्य चुनौतियाँ:

धन का दुरुपयोग:

- यह गंभीर चरचा का वषिय है कि क्या ग्रीन बॉण्ड जारी करने वालों द्वारा लक्षित परयोजनाएँ प्रयाप्त रूप से हरति परयोजनाएँ ही हैं क्योंकि ग्रीन बॉण्ड से प्राप्त आय का उपयोग प्रयावरण को नुकसान पहुँचाने वाली परयोजनाओं के वित्तिपोषण हेतु कयि जा रहा है।

क्रेडिट रेटिंग का अभाव:

- हरति परयोजनाओं और बॉण्डों के लयि क्रेडिट रेटिंग या रेटिंग दशा-निरिदेशों का अभाव है।

अलपावधि:

- भारत में ग्रीन बॉण्ड की अवधि लिगभग 10 वर्ष होती है, जबकि एक सामान्य ऋण की न्यूनतम अवधि 13 वर्ष होती है। इसके अलावा ग्रीन प्रोजेक्ट्स का लाभ मलिने में भी अधिक समय लगता है।

आगे की राहः:

- सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक ग्रीन बॉण्ड बाजार को वकिसति करने के लयि अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू दशा-निरिदेशों एवं मानकों के साथ सामंजस्य स्थापति करना है। हरति नविश के संदर्भ में भी समरूपता की आवश्यकता होती है, क्योंकि विभिन्न कर-सीमाएँ एक निधारति सीमा से परे ग्रीन बॉण्ड बाजार के लयि वरिधाभासी होंगी।
- उभरते बाजारों में जारीकरताओं के लयि उच्चि क्षमता निमाण का प्रयास, जो ग्रीन बॉण्ड से संबंधित लाभों और प्रक्रयियाओं की जानकारी प्रदान करते हों, इस बाजार में प्रवेश करने हेतु संस्थागत बाधाओं को दूर करने में सहायक होगा।
- रणनीतिक रूप से ग्रीन बॉण्ड के संदर्भ में सार्वजनिक क्षेत्र का नविश नजी नविश को आक्रसति करने और साथ ही ग्रीन बॉण्ड बाजार में नविशकों का वशिवास स्थापति करने में मदद करता है।

स्रोतः इंडियन एक्सप्रेस